THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) No comprehensive survey covering entire Delhi has been conducted by the Directorate of Social Welfare, Delhi. However, a survey conducted by the Department of Social Welfare, Delhi Administration in 1988 in Slum and resettlement areas in Delhi revealed that there were 2608 drug addicts.

(b) Does not arise.

(c) Government is providing financial assistance to voluntary organisation for founding Counselling, De-addiction and After Care Centres as also for awareness building programmes. Electrinic and print media is also being used for awareness building.

Ministerial level talks between India and Bangladesh on sharing of river waters

@@*176. SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the outcome of the Ministrial level talks held between India and Bangladesh in Delhi in April, 1992 regarding the sharing of river waters between the two countries;

(b) whether any progress has been made towards resolving the disputes between the two countries;

(c) what subjects were discussed; and

(d) whether any furhter round of talks will be held; if so, when

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (c) The Minister for Agriculture, Irrigation, Flood Control and Water Development, Bangladesh held discussions with Minister of Water Resources, India on 21st and 22nd April, 1992. The Indian side suggested for sharing of river waters on a comprehensive basis in an integrated manner for consideration by Bangladesh.

(d) The next round of talks will be held on dates convenient to the two countries.

@@Previously Starred Question 96, transferred from the 4th May, 1992.

Implementation of Metro Plan in Delhi

*177. SHRI GHUFRAN AZAM: SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item captioned "Delhi Metro Plan in doldrums" which appeared in the Hindustan Times dated the 26th April, 1992;

(b) whether there is continuous increase in traffic in the Capital; and

(c) if so, the steps taken by Government to implement the Delhi's Metro Plan?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) To release congestion on Delhi roads, Delhi Administration got a techno-economic feasibility study conducted from M/s Rail India Technical and Economic Services Ltd. (RITES). The study has recommended introduction of the an integrated multi-mode rapid transit system coverng a total distance of 184.5 Kms. including underground metro corridors for a distance of 27 Kms. at an estimated cost of Rs. 5377 crores at 1989 price level. The project of this magnitude involves legal, financial and land use implications.

A High Powered Committee under the Chairmanship of Lt. Governor of Delhi has been constituted to go into various aspects including setting up of a single Transport Authority as also identifications of funds for the construction of projects.

The government is also exploring the possibilty of funding the project on Build, Operate and Transfer (BOT) Basis.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए छात्रावास तथा अन्य सुविधायें

*178 मौलाना ओबदुल्ला खान आजमी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए छात्रावास;

पुस्तकालय, वाचनालय, चिकित्सा, पठन-पाठन और भोजन की सुविधाएं अपर्याप्त और निम्न-स्तर की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के दो आवासीय हाल हैं जिसमें महिलाओं के लिए 8 छात्रावास शामिल हैं । इनमें से एक आवासीय हाल में रसोई की सुविधाओं और महिला कालेज के पुस्तकालय में सुधार की पर्याप्त आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 8वीं योजना अवधि के दौरान आवश्यकता निधियां प्रदान की जाएंगी । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के आठवीं योजना के अपने विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 300 स्थान वाले एक महिला छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव किया है। विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा कालेज द्वारा सभी छात्रों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

सुवर्ण रेखा परियोजना के विस्थापितों को बसाया जाना

@@@*179. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुवर्ण रेखा के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप विस्थापित लोगों को न तो अभी तक बसाया गया है और न ही उन्हें कोई मुआवजा दिया गया है ;

(ख) क्या मुआवजे की राशि के वितरण में बहुत अनियमितताएं की गई ह,

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से प्रभावित परिवारों को विस्थापित परिवारों की सूची में शामिल नहीं किया गया है;

(घ) क्या विस्थापितों को बसाने के लिए बहुत कम जमीन दी गई है तथा बड़ी संख्या में लोग बिना कोई मुआवजा दिये विस्थापित किये जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपनी भूमि आदि से संबंधित कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसे कोई मामले नहीं लाए गए हैं । विस्थापित व्यक्तियों को प्रदान की गयी राहत और पुनर्स्थापन से सम्बन्धित स्थिति दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है (**नीचे देखिए**) सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनी परियोजना में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुन-स्थापन का मार्ग-निर्देश दिसम्बर, 1990 में बिहार सरकार द्वारा प्रतिपादित संशोधित पुनर्वास नीति द्वारा किया जाता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

सुवर्ण रेखा बहु परियोजना परियोजना में राहत और पुनर्स्थापन का ब्यौरा :

क्रम सं०	मद	चंडिल बांध	इचा बांध
1	जलाशय के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर)	17,611	9,763
2.	अर्जित क्षेत्र (हेक्टेयर)	11,465	2,918
3.	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)	116	87
4.	गांव जिनमें राहत प्रदान की गयी	86	26
5.	प्रभावित परिवार	9,820	2,218
6.	परियोजना में रोजगार	1,159	277

@@@पूर्वतः तारांकित प्रश्न, 119, 5 मई, 1992 से स्थानांतरित ।